

“भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भूगोल का एक विषय के तौर पर उत्थान की विवेचना”

विश्वनाथ सैदावत

सहायक आचार्य, बियानी गर्ल्स कॉलेज, जयपुर

शोध सारांश:

देखा जाए तो प्राचीन काल से ही भारतीय शास्त्रों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत में भूगोल विषय से संबंधित शोध के साक्ष्य पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भारत में कब से भूगोल विषय के तौर पर नींव रखी गई? भूगोल विषय के अध्ययन की प्रगति किस प्रकार से रही? भारत के भौगोलिक संसाधनों के उपयोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? प्रस्तुत शोध पत्र में इस विषय पर विवेचना की गई है।

परिचय:

यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से अद्वितीय है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में सागर-महासागरों से घिरा यह भौगोलिक क्षेत्र, अपनी विशेषताओं की वजह से उपमहाद्वीप भी कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाले भौगोलिक क्षेत्र होते हुए भी भारत न तो अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन में आत्मनिर्भर बन पाया वरन् अन्य देशों पर निर्भरता स्वतंत्र रूप से बनी हुई है। कारण रहा- यहां प्राकृतिक संसाधन भूगोल पर पर्याप्त शोध का न होना। सघन जनसंख्या होने के बावजूद न तो मानव भूगोल विषय पर अधिक ध्यान दिया, न ही मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर अनुसंधान हुए। हम स्वतंत्रता पूर्ण भारतीय इतिहास में शायद ही किसी भारतीय भूगोलवेत्ता को वैश्विक स्तर पर पाते हैं। नीति-नियंता, अधिकारियों द्वारा एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किए जाने से भूगोल एक विषय के रूप में निम्नतम रुचिकर विषयों के रूप में जाना गया या फिर एक गैर-उपयोगी विषय के रूप में। जबकि अन्य विकसित देशों में यह है पूरे राष्ट्र के विकास की गति को प्रभावित करते देखा गया है।

भूगोल विषय का भारत में प्रादुर्भाव :

यद्यपि भारत में भूगोल से संबंधित सोसाइटी 1832 मुंबई ज्योग्राफिकल एसोसिएशन थी। लेकिन भारत के शिक्षण संस्थानों में भूगोल एक विषय के रूप में सर्वप्रथम 1920 में पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शामिल हुआ। तत्पश्चात 1927 में पटना विश्वविद्यालय और 1928 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूगोल विषय का प्रसार हुआ। इनमें से अधिकतर शुरुआती वर्षों में 1 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों के रूप में शुरू हुआ। लगभग 1950 के दशक तक भूगोल का विकास मंद रहा। यद्यपि 1941 में कोलकाता विश्वविद्यालय 1946 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1947 में आगरा व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, 1948 में मद्रास विश्वविद्यालय में और 1957 में मुंबई विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना हुई। गौरतलब है कि जहां 1920 के दशक में उत्तर भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल का प्रादुर्भाव हुआ, वही दक्षिण भारत में 1950 के दशक में पहुंचा। कह सकते हैं कि लगभग एक चौथाई शताब्दी भूगोल विषय को उत्तर से दक्षिण की यात्रा करने में लग गया। यदि हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि उत्तर भारत में गंगा प्रवाह क्षेत्र या फिर कहे कि गंगा के मैदान उससे सटे क्षेत्रों में भूगोल को अभिभावक एक सामान्य ज्ञान के विषय के रूप में छात्र को दिलाना पसंद करते हैं क्योंकि संबंधित राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल विषय से अच्छी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः उत्तर भारत में भूगोल विषय से संबंधित संस्थान वह छात्र दोनों ही

दक्षिण भारत की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। परिणामतः यह भी सामने आता है कि उत्तर भारत में संसाधनों का प्रबंधन अपेक्षाकृत उच्च स्तर का प्रतीत होता है। वहीं दक्षिण भारत में भूगोल का प्रसार अधिक नहीं है अभिभावक भी विज्ञान व प्रौद्योगिकी विषयों को प्राथमिकता देते हैं परिणामतः देखा गया कि दक्षिण राज्यों में संसाधनों का प्रबंधन अपेक्षाकृत निम्न स्तरीय है जो आज के संदर्भ में चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है।

भारत में भूगोल संबंधित बड़े कदम :

हालांकि भूगोल विषय की भारत में कोई क्रांतिकारी पहल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए जोकि भूगोल के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हुए। इन कदमों में पहला कदम था- 1928 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना। इसके बाद प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय एटलस संगठन' (एन ओ ए) की स्थापना हुई, जिसे आजकल हम 'नेशनल एटलस एंड थीमैटिक ऑर्गेनाइजेशन (एन ए टी एम ओ) के नाम से भी जाना जाता है।' सर्वे ऑफ इंडिया' के बाद यह भारत का सबसे प्रसिद्ध मानचित्रण संगठन है, जिसकी 'दस लाख शृंखला' विख्यात रही है। 1960 में 'फ्रांसीसी संस्थान, पांडिचेरी' (अब पुदुचेरी) द्वारा कार्टोग्राफी इकाई स्थापित की गई, जिसने 1:100000 पैमाने पर वनस्पति और संसाधनों का मानचित्रण करके ख्याति पाई। इस इकाई को 1995 में ज्योमेटिक्स प्रयोगशाला में उन्नत कर दिया गया, जिसमें कंप्यूटर कार्टोग्राफी और जीआईएस पर बल दिया गया। 1968 में 21 वा 'भौगोलिक संघ सम्मेलन' नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जहां भारतीय भूगोलवेत्ताओं को अंतरराष्ट्रीय ख्यातनाम भूगोलवेत्ताओं से परिचित होने का अवसर मिला और भारतीयों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अनुसंधान और शोध के मार्ग प्रशस्त हो गए। 1970 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के 'क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र' की स्थापना हुई, जिसने भारत में भौगोलिक अनुसंधान को एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। इसने भारतीय भौगोलिक अध्ययनों के 'भारतीयकरण', भूगोल की अस्तित्व के लिए भौगोलिक अनुसंधान की 'सामाजिक प्रासंगिकता' पर बल दिया। आगे 1980 में 'राष्ट्रीय भूगोलवेत्ता संघ', भारत (एन ए जी आई) की स्थापना ने सभी भारतीय भूगोलवेत्ता को एक छत के नीचे ला दिया जोकि एक बहुत बड़ा कदम के तौर पर देखा जाता है। इसमें प्रोफेसर मुनीस रजा (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली), प्रोफेसर सी.डी. देशपांडे (मुंबई विश्वविद्यालय), प्रोफेसर एल. एस. भट्ट (भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली), जैसी विभूतियों का अविस्मरणीय योगदान रहा।

भारत में ज्योग्राफिकल सोसाइटी :

भारत में लगभग 190 वर्ष पूर्व ही पहली ज्योग्राफिकल सोसाइटी अस्तित्व में आ चुकी थी। 1832 में मुंबई ज्योग्राफिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसे 1873 में 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी' में विलय कर दिया गया। 1925 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल के प्रचार एवं प्रसार की नई राह दिखाई। तत्पश्चात 1926 में इंडियन ज्योग्राफिकल सोसायटी मद्रास (अब चेन्नई) की स्थापना ने भारत में भूगोल के प्रचार प्रसार में क्रांति ला दी। इस सोसाइटी ने 1926 में ही अपनी जर्नल 'द मद्रास ज्योग्राफिकल जर्नल' (अब इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल) प्रकाशित की। इंडियन ज्योग्राफिकल सोसायटी मद्रास के हर जिले में 'क्षेत्रीय भूगोल' के विषय पर संगोष्ठी करवाई, क्षेत्रीय भूगोल पर शोध पर प्रकाशित किए जिससे कि भूगोल को एक विषय के तौर पर लोकप्रियता मिली। 1933 में कोलकाता विश्वविद्यालय की 'कोलकाता ज्योग्राफिकल सोसायटी' की स्थापना और 1936 में इसने 'ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया' नामक जर्नल प्रकाशित की। 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 'नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया' प्रकाशित किया।

इन सभी सोसाइटी ने प्रोफेसर आर. एल. सिंह के सानिध्य में भूगोल के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। भारत में अन्य बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो भूगोल के प्रचार में अनुसंधान में और शोध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी महती भूमिका निभाते हैं। यद्यपि उनका मूल कार्य भिन्न हो, वे भौगोलिक अनुसंधानों के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने में अतुलनीय भूमिका निभाते हैं, जैसे राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संस्थान (एन ए टी एम ओ), भारत की जनगणना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान

परिषद, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), नीति आयोग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि परिषद आदि।

भूगोल के विभिन्न शाखाओं का विकास :

भौतिक भूगोल: भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों जहां पर भूगोल विभाग स्थापित हो वहां भू-आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान को स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है लेकिन भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान में अनुसंधान क्षेत्र बहुत सीमित रह गया है हालांकि कुछ समय से वैश्विक तापन के प्रभाव, खाद्यान्न जरूरतों के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी सुदूर संवेदन तकनीकी की सहायता से भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान में अनुसंधान के नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। नदी प्रवाह क्षेत्र, मिट्टी के वर्गीकरण, पुनर्युवन या हिमनदों के अध्ययन हेतु इस क्षेत्र में नई मात्रात्मक क्रांति आई है। रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ई.अहमद की तटीय भू-आकृति के क्षेत्र में, पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के. आर. दीक्षित को स्थलरूप विकास के क्षेत्र में, प्रोफेसर सविंदर सिंह को प्रवाह भू-आकृति के क्षेत्र में और प्रोफेसर पद्मजा को उष्णकटिबंधीय भू-आकृति के क्षेत्र में, प्रोफेसर वैद्यनाथन को सुदूर-संवेदन की सहायता से भू आकृतियों की पहचान के अध्ययन क्षेत्र में आदर पूर्वक दृष्टि से देखा जाता है। भारत ही सुदूर संवेदन एजेंसियों- भू विज्ञान अध्ययन केंद्र (केरल), केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी, राजस्थान) असम विश्वविद्यालय ने भी भू-आकृति अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभाई है।

पर्यावरण व संसाधन अध्ययन: आधुनिक समय में पर्यावरण और संपोषणीय विकास के क्षेत्र ने अध्ययनकर्ताओं का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया है। संसाधनों का अनुचित दोहन ने पर्यावरण और भविष्य की जरूरतों पर विशेष नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। भारत आज वैश्विक पटल पर पर्यावरण हितैषी देश के रूप में उभरा है। सुदूर संवेदन एजेंसियों संस्थानों ने इस क्षेत्र में अनुसंधान को नई दिशा दी है। यह क्षेत्र आज भारत को विश्व गुरु के रूप में फिर से उभरने में सहायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि प्राचीन भारतीय विचारों ग्रंथों में पर्यावरण व संसाधनों का उचित दोहन पर बल रहा और अति दोहन से बचने का विचार भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है।

मानव व आर्थिक भूगोल:जैसा कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है। ऐसे में कृषि यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है और सर्वाधिक रोजगार सृजक क्षेत्र भी। अतः इस क्षेत्र में अनुसंधान आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। भू-उपयोग, फसल संयोजन, फसल और कृषि क्षेत्र, फसल उत्पादकता, कृषि दक्षता व पोषण आदि पर अध्ययन जारी है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र ने कृषि उत्पादकता और विकास के क्षेत्र, क्षेत्रीय-अंतर पर अध्ययन किया। कृषि क्षेत्र, क्षेत्रीयता के मात्रात्मक पद्धति वह वाँन थुनेन की 'फसल स्थान और कृषि उत्पादकता सिद्धांत' ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल नेताओं का भूगोलवेत्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शहरी व ग्रामीण बस्ती भूगोल पर अपने काम के लिए जानी जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अधिकतर भूगोलवेत्ताओं पर अमेरिकी शहरी बसावट पद्धतियों का असर अधिक दिखता है। मद्रास विश्वविद्यालय स्थानिक विश्लेषण और शहरी पारिस्थितिकी पर व हैदराबाद की उस्मानिया विश्वविद्यालय महानगरीय अर्थव्यवस्था शहरी व औद्योगिकीकरण पर अध्ययन के लिए जानी जाती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र ने बी.जे.एल. बेरी के भारत में वस्तु- प्रवाह के विश्लेषण से भारत में व्यापार और परिवहन पर मात्रात्मक अध्ययन का अनुकरण किया है। भारत में जनसांख्यिकी ने भी भूगोलवेत्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। 'भारत की जनगणना' ने इसके लिए पर्याप्त डेटाबेस उपलब्ध करवाया। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ने जनसंख्या भूगोल पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय जनसांख्यिकी का क्षेत्रीय-अंतर इस क्षेत्र के सामान्य विषय रहे हैं।

उपसंहार :

21वीं शताब्दी में भौतिक भूगोल में शोध या अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो गया है। कई भूगोल विभागों में तो सर्वेक्षण उपकरणों को दरकिनार कर दिया गया है। यद्यपि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है लेकिन

भूगोलवेत्ता वातानुकूलित कक्षों से ही फील्ड वर्क की खानापूति कर देते हैं या फिर फील्ड वर्क सैर सपाटा के अवसर मात्र बनकर रह गए हैं। भूगोलवेत्ताओं में कार्टोग्राफी कौशल अप्रत्याशित रूप से घट रहा है जिस वजह से कार्टोग्राफी का कार्य डाफ्ट्समैन के भरोसे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) व नई सूचना प्रौद्योगिकी ने भूगोलवेत्ताओं को आकर्षित किया है। सुदूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी के आपसी सहयोग से शोधों में सटीकता व तथ्यात्मकता बढ़ी है। इससे समय बचत के साथ-साथ अन्य भूगोलवेत्ताओं से शोध के बारे में परामर्श, विचार-विमर्श करने से शोध व अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता का वर्धन हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभागों का प्रशासन किया जाना व शिक्षाविदों के परामर्श के बिना विषयों के पाठ्यक्रम तय किया जाना, विभागीय फैसलों में किसी भी शैक्षिक मापदंडों, गाइडलाइन, अन्य देसी-विदेशी विश्वविद्यालयों से परामर्श के अभाव में उच्च अधिकारी स्वविवेक से ही शैक्षिक पद्धतियों, शैक्षिक पाठ्यक्रम को तय कर देते हैं जो कहीं ना कहीं शैक्षिक गुणवत्ता ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यद्यपि नई शिक्षा नीति (एनईपी) से इसमें सुधार की व्यापक संभावना प्रकट हुई है। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में खुलापन आया है जिससे कि अंतर-विषयों में सामंजस्य स्थापित होगा। भूगोल और विज्ञान के क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित होगा जोकि भूगोल विषय को संभावित नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होगा। अनुसंधान के अधिकतर क्षेत्रों में पहुंच संभव हो पाएगी। अनुसंधान व शोध कार्य में हालिया बदलाव प्रभावी सिद्ध होंगे ऐसी आशा है।

संदर्भ सूची:

1. चटर्जी, एस. पी. (1960). *भारत का भूगोल: एक समग्र अध्ययन*. कोलकाता: नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन (NATMO).
2. सिंह, आर. एल. (1971). *भारत: क्षेत्रीय भूगोल*. वाराणसी: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रेस.
3. अहमद, ई. (1985). *तटीय भू-आकृति विज्ञान*. रांची: रांची विश्वविद्यालय प्रकाशन.
4. दीक्षित, के. आर. (1990). *स्थलरूप विकास: सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण*. पुणे: पुणे विश्वविद्यालय प्रेस.
5. सर्विंदर सिंह (1995). *प्रवाह भू-आकृति: भारतीय संदर्भ*. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.
6. रजा, मुनीस (1982). *भारत में क्षेत्रीय विकास: एक भौगोलिक दृष्टिकोण*. नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रकाशन.
7. भट्ट, एल. एस. (1975). *भारत में क्षेत्रीय नियोजन*. नई दिल्ली: भारतीय सांख्यिकी संस्थान.
8. देशपांडे, सी. डी. (1992). *भारत में भूगोल का इतिहास*. मुंबई: मुंबई विश्वविद्यालय प्रेस.
9. इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी (1926-). *इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल*. चेन्नई: इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी.
10. कोलकाता ज्योग्राफिकल सोसाइटी (1936-). *ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया*. कोलकाता: कोलकाता विश्वविद्यालय.
11. नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया (1946-). *राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका*. वाराणसी: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय.
12. भारत सरकार (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020*. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.
13. सर्वे ऑफ इंडिया (2000). *भारत के मानचित्र: ऐतिहासिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य*. देहरादून: सर्वे ऑफ इंडिया.
14. फ्रांसीसी संस्थान, पुदुचेरी (1995). *कार्टोग्राफी और जियोमैटिक्स: भारतीय अनुसंधान*. पुदुचेरी: फ्रांसीसी संस्थान.
15. कृष्ण, गोपाल (1988). *जनसंख्या भूगोल: भारतीय परिप्रेक्ष्य*. चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय प्रकाशन.